E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

सहरिया जनजाति में कुपोषण की समस्या एवं आहार अनुदान योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(श्योपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

सविता शर्मा

शोधार्थी (भूगोल), जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

डॉ. श्रीमती रंजना दीक्षित

मार्गदर्शक,से.नि. प्राध्यापक (भूगोल),माधव महाविद्यालय ग्वालियर

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11237351

सारांश :

आज भारत में कुपोषण की समस्या एक विकराल समस्या है। सरकारी ऑकड़ों से स्पष्ट है कि करोडों लोगों को भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को पेट की भूख मिटाने के लिए मुफ्त में भोजन देना पड़ रहा है ऐसे परिवारों के लिए पौष्टिक आहार की कल्पना कैसे की जा सकती है जो पेट की अग्नि बुझाने के लिए भी सरकार पर निर्भर है। जनजातियों में तो यह समस्या और भी विकट है। शोधार्थिनी का विषय सहरिया जनजाति से है जो मध्यप्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। सहरिया जनजाति में कुपोषण समस्या बहुत अधिक है क्योंकि यह जनजाति आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है। सहरिया जनजाति की गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। फलस्वरूप नवजात शिशु जन्म से ही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति हेतु आहार अनुदान योजना संचालित की, जो इन जनजातियों की कुपोषण की समस्या को दूर करने में सहायक हो रही है। शोधार्थिनी ने अपने अध्ययन में पाया है कि यद्यपि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीबी एवं कुपोषण की समस्या के निदान हेतु कई योजनाएँ जैसे एन.सी.आर. आहार अनुदान, अन्त्योदय अन्न योजनाएँ चलाई जा रही है किन्तु अन्धविश्यास एवं शिक्षा का अभाव होने के कारण सहरियाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है जो इनके कुपोषण के निदान में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

मुख्य शब्द: कुपोषण, सहरिया जनजाति, शिक्षा का अभाव, गरीबी, जागरूकता, आहार अनुदान योजना।

भारत में आज भी कुपोषण की समस्या विकराल है जिनमें आदिवासियों की स्थिति और भी गम्भीर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, खेती, आदि क्षेत्रों में आदिवासी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वे आज भी भर पेट भोजन नहीं ले पाते हैं। पौष्टिक भोजन का तो यहाँ अभाव ही रहता है। अतः यहाँ पर अधिकतर गर्भवती महिलाएँ एवं शिशु कुपोषण का शिकार पाए जाते हैं। कुपोषण वह स्थिति है जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्त्व उपलब्ध नहीं हो पाते है अर्थात शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्त्वों प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आयरन, कैल्शियम आदि की कमी होना ही कुपोषण है।

मध्यप्रदेश की सबसे अधिक पिछड़ी जनजाति सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनकी जीवन शैली में आज भी प्राचीन परम्पराओं, आदिम प्रवृत्तियों का सहज ही प्रचलन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास व्यवस्था आदि का अभाव है। सहरिया मूलतः एक ऐसी जनजाति है जो जंगलों पर निर्भर है। इसी कारण आज भी अधिकांश सहरिया लोग अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन कृषि मजदूरी, शिकार एवं पशुपालन

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

द्वारा ही करते हैं। इनकी कृषि भी परम्परागत व्यवस्था पर आधारित है। अतः इनके जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता है। धनाभाव के कारण पौष्टिक आहार तो दूर की बात है कभी–कभी तो ये भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते हैं। सहरियाओं में गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन न मिल पाने के कारण वे कुपोषण का शिकार रहती है एवं कुपोषित बच्चों को ही जन्म देती है।

भारत में 5 वर्ष से कम आयु के आदिवासी बच्चों में 40% बौने होते हैं. 16% गम्भीर रूप से बौने होते है. 22% बच्चे कम वजन के साथ जन्म लेते है. 1000 बच्चों में से 50 बच्चे अपने जीवन का पहला वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जन्म से 3 माह तक के 79% बच्चे आयरन की कमी का शिकार हैं। बच्चों की इस स्थिति के लिए गर्भवती महिलाएँ अधिक जिम्मेदार होती है क्योंकि जब गर्भवती महिला स्वय कुपोषित होगी तो वह स्वस्थ बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? अतः स्वस्थ बच्चों के जन्म के लिए गर्भवती महिला का स्वस्थ होना अनिवार्य है। आदिवासियों में 36% महिलाएँ कम वजन की है, 44% महिलाएँ दुबली हैं, 56% महिलाएँ आयरन की कमी के कारण एनीमिया (खून की कमी) का शिकार है।

कुपोषण क्या है? जब यह समझ में आ जाता है तो फिर इस समस्या का निदान कैसे किया जाय, यह प्रश्न उठता है। इसके कारकों को समझकर लोगों को जागृत करना तथा सरकारी प्रयास करना अनिवार्य हो जाता है। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार कुपोषण के निदान हेतु काफी प्रयास कर रही है। शोध समस्या का चयन

शोधार्थिनी ने श्योपुर जिले की सहरिया जनजाति का अध्ययन किया तथा पाया कि सहरियाओं में अनेक समस्याएँ व्याप्त है जिनमें एक प्रमुख समस्या कुपोषण की समस्या है जो उनके विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। यह एक बहुत ही गम्भीरता का विषय है। इस समस्या को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर शोधार्थिनी ने अपने शोध–पत्र में प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध अध्ययन श्योपुर जिले की सहरिया जनजाति पर आधारित है। प्रस्तुत शोध में सहरिया जनजाति में व्याप्त कुपोषण की समस्या का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है–

- सहरिया जनजाति का अध्ययन करना।
- सहरिया जनजाति में कुपोषण की स्थिति का पता लगाना।
- आहार अनुदान योजना का ऑकलन करना एवं योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्या का पता लगाना।
- सहरियाओं में आहार अनुदान योजना के प्रति जागरूकता का पता लगाना।
- लाभार्थी महिलाओ को प्राप्त अनुदान सहायता से परिवार के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति का पता लगाना।
- सहरिया जनजाति में आहार अनुदान योजना के प्रति जागरूकता का पता लगाना।

विधि तंत्र :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सामाजिक शोध के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है। शोध का अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश का श्योपुर जिला है। अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाली सहरिया जनजाति के समस्त परिवारों को अध्ययन के समग्र में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन इकाई के रूप में सहरिया जनजाति की 450 महिलाओं को

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

उत्तरदाताओं की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है। श्योपुर जिले के 30 सहरिया बाहुल्य गाँव का चयन किया गया। प्रत्येक गाँव से 15 सहरिया परिवार की महिलाओं का चयन किया गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु स्वयं के द्वारा साक्षात्कार अनुसूची एवं प्रत्यक्ष सामूहिक चर्चा, स्व अवलोकन कर प्राथमिक आँकड़ों का संकलन किया गया तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित अभिलेखों से द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया। संकलित आँकडो का वैज्ञानिक विधि द्वारा वर्गीकरण, सारणीयन कर आँकड़ों का विश्लेषण किया गया।

आहार अनुदान योजना :

मध्यप्रदेश सरकार ने जनजातियों के उत्थान हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की है. उन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है आहार अनुदान योजना । यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहरिया, वैगा एवं भारिया जनजाति के कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु विशेष रूप से चलाई गई है। इस योजना का प्रारम्भ 23.12.2017 को मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस योजना के अन्तर्गत विशेष पिछडी जनजाति (बैगा, मारिया एवं सहरिया) परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में कुपोषण मुक्ति हेतु 1000/– रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाती है। यह योजना मध्यप्रदेश के 15 जिलों में संचालित है, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मण्डला, बालाघाट, छिन्दवाडा, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर।

विशेष पिछडी जनजाति विकास हेतु प्रदेश स्तर पर तीन प्राधिकरण गठित है। सहरिया विकास प्राधिकरण बैगा विकास प्राधिकरण एवं भारिया विकास प्राधिकरण। प्रदेश में विशेष पिछडी जनजाति बाहुल्य 15 जिलों में 11 अधिकरण गठित है।

सारणी क्रमांक–1

विशेष पिछड़ी जनजाति प्राधिकरण, मुख्यालय एवं जिला

क्र	प्राधिकरण	मुख्यालय	जिला क्षेत्र		सख्या
(अ)	सहरिया विकास प्राधिकरण	1. श्योपुर 2. ग्वालियर 3. शिवपुरी 4. गुना	श्योपुर, मुरैना, मिण्ड, ग्वालियर दतिया, शिवपुरी,गुना,अशोकनगर		417171
(ब)	बैगा विकास प्राधिकरण	1. शहडोल 2. अनूपपुर 3. उमरिया 4. मण्डला 5. डिण्डौरी 6. बालाघाट			131425
(स)	भारिया विकास प्राधिकरण	1. तामिया 2. छिन्दवाडा	छिन्दवाडा के तामिया के 12 गाँव		2012

स्रोत : प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2017–18, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

सारणी क्रमांक–2

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

आहार अनुदान योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में बजट वितरण

स क्र	वर्ष	बजट वितरण (रूपयो में)	लाभार्थी महिला संख्या	कुल व्यय
1	2017–18	83.112 करोड़ (दिसम्बर माह से)	–	83112 करोड़
2	2018–19	174.693 करोड	242752	174.693 करोड
3	2019–20	149.455 करोड	224058	149.455 करोड
4	2020–21	311.32 करोड	237251	149.455 करोड
5	2021–22	270.00 करोड	230242	149.455 करोड
6	2022–23	290.00 करोड	239741	210.12 करोड़ (नवम्बर–2022 तक की स्थिति)

सारणी क्रमांक–3

आहार अनुदान योजना की लाभार्थी सहरिया महिलाओं की जानकारी

क्रमाक	लाभ की स्थिति	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	ळां	312	69.33
2.	न्हीं	105	23.33
3.	कभी–कभी	33	07.34
	योग	450	100

सारणी क्रमांक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 450 सहरिया महिलाओं में से 312 (69.33%) सहरिया महिलाएँ आहार अनुदान योजना का लाभ ले रही है, 105 (23.33%) महिलाएँ आहार अनुदान योजना का लाभ नहीं ले पा रही है क्योंकि शिक्षित न होने के कारण तथा गाँव की भौगोलिक स्थिति पथरीली एवं शहर से बहुत दूर है जहाँ शासकीय योजनाओं के संचालन में समस्या देखने को मिलती है। 33 (07.34%) महिलाएँ को कभी–कभी इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाता है. क्योंकि कभी खाते से सबंधित समस्या तथा आँकडा अद्यतन की कमी के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर सहरिया महिलाएँ आहार अनुदान योजना का लाभ ले रहीं है।

सारणी क्रमांक–4

क्या आहार अनुदान योजना में प्रतिमाह दी जाने वाली 1000/– रूपये की राशि कुपोषण के निदान के लिए पर्याप्त है ?

क्रमांक	विकल्प	लाभार्थी महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	ळां	21	69.33
2.	न्हीं	324	23.33
	योग	345	100

लाभार्थी महिलाओं की संख्या प्रतिशत:

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

सारणी क्रमांक 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 345 सहरिया महिलाओं में से 21 (06.09%) ने स्वीकार किया कि आहार अनुदान योजना में प्रतिमाह दी जाने वाली 1000/– रूपये की राशि कुपोषण के निदान में पर्याप्त है किन्तु 324 (93.91%) सहरिया महिलाओं का मानना है कि यह राशि पर्याप्त नहीं है. क्योंकि 1000/– रूपये तो मिलते है पर परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, कुछ परिवारों में संयुक्त परिवार भी देखने को मिले हैं तथा कागजों की कमी के कारण भी 1000/– रूपये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आहार अनुदान योजना में दी जाने वाली राशि कुपोषण की मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

निष्कर्ष :

सहरिया जनजाति में कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है लेकिन शासन के प्रयास से अब यह समस्या गम्भीर नहीं रह गई है। भुखमरी की समस्या सामान्य है प्रमुख समस्या कुपोषण है जिसका कारण शिक्षा का अभाव एवं जागरूकता की कमी है। शासकीय योजनाओं में प्रयास किए जा रहे है जिनमें आहार अनुदान योजना प्रमुख है। भुखमरी की समस्या के मुख्य कारण निम्न हैं–

1. जागरूकता का अभाव
2. योजनाओं की अनभिज्ञता अर्थात् लोगों में योजना की जानकारी नहीं है जिन्हें जानकारी है भी वे इसके प्रति अधिक जागरूक नहीं है।
3. शोधार्थिनी ने पाया कि इस योजना के माध्यम से सहरियाओं के कुपोषण की स्थिति में कमी अवश्य हुई है किन्तु यह राशि कम है. साथ ही सहरियाओं में कुपोषण एवं आहार अनुदान योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता भी है।

सुझाव :

सहरियाओं में कुपोषण की समस्या समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव है –

1. शासन द्वारा इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएँ चलाई जा रही है उनके प्रचार–प्रसार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
2. शासकीय योजनाओं के प्रति सहरिया समाज में विश्वसनीयता को बढ़ावा देना चाहिए।
3. ये लोग अन्य लोगों के साथ बातचीत या सम्पर्क करने से डरते हैं। अतः योजनाओं का संचालन इन्हीं के समाज के व्यक्तियों से करवाना चाहिए जिससे ये योजनाओं का सही लाभ उठा सकें।
4. स्वास्थ्य सेवाएँ घर–घर तक पहुँचाना चाहिए ताकि बच्चों की चिकित्सा ओझाओं द्वारा न की जाए।
5. शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जो प्रत्येक समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है अतः प्रत्येक सहरिया को शिक्षित करना शासन का उददेश्य होना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. निरगुणे, बसन्त (2004), मध्यप्रदेश की जनजातियों, महावीर पब्लिशर्स, इन्दौर।
2. अमानुल्लाह, मोहम्मद (1997), सहरिया जनजाति का संक्षिप्त मानव शास्त्रीय अध्ययन, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
3. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2017–18, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022–23, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

5. शर्मा, श्रीनाथ (2014), जनजातीय समाजशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
6. उप्रेती, डॉ हरीशचन्द्र (2002), भारत की जनजातियाँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।